छिपाना नहीं चाहता हूं । अगर कोई आरोप है, कोई घोटाला है तो उस घोटाले को किसी भी हद तक इस सरकार की तरफ़ से आश्रय नहीं दिया जा सकता है । छिपाने की कोई कोशिश नहीं की जा सकती है । मेरी जानकारी नहीं है, मैंने जहां तक देखा है, न मैंने श्री बसंत साठे जी की कोई टिप्पणी देखी है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, लेकिन जिस एन०टी०पी०सी० के अधिकारी का नाम लिया गया है, हां उस अधिकारी की टिप्पणी मैंने जरूर देखी है जिसमें प्राइस डिफ़रेंस के बारे में बात करते हुए यह कहा गया है जो प्राइस का डिफ़रेन्स है, उस निश्चित प्रस्ताव का टेक्नीकल कंफ़िगरेशन है वह हमारे बिड के जो स्पेसिफ़िकेशन्स हैं उसके अनुसार नहीं है । इस मामले में मुझे जितनी जानकारी है, मैंने पहले कहा है कि उसके आगे जो कागजात हैं वे मैंने बताये हैं । मेरा सिर्फ़ कहना यह है कि आरोप लगाते वक्त जरा संजीदगी के साथ थोड़ा अपने आप में सन्तुष्ट कर लिया जाय । यहां पर कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की गई है । लेकिन जब आप घोटाला कह दें तो फ़िर मुझे पक्का यकीन है कि आपके पास वह कागज मौजूद होने चाहिए जिनसे आप साबित कर सकें कि घोटाला है । ऐसे ही घोटाला कह देने से घोटाला नहीं हो जाता । अभी यहां सवाल आ रहा था, आज स्थिति यह है कि पावर सर्वे कमेटी ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 48 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया था । प्लानिंग कमीशन, 1987 में कहा कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं, 48 हजार के आगे मत जाइएगा। आपने सवाल पूछा कि बी०एच०ई०एल० की उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है । स्थिति यह है कि शायद 26–27 हजार मेगावाट तक भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इतना पैसा भी उपलब्ध कराना कठिन होगा । अभी तक उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है । मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य ने पूछा कि इसमें क्या मजबूरी है ? मेरी मजबूरी यह है कि जो प्रोजेक्ट साल भर डिले हो जाती है उसके साल डेढ़ साल डिले होने पर सौ; डेढ़ सौ करोड़ रुपए इतनी क्षमता की प्रोजेक्ट पर खुद-ब-खुद बढ़ जाते हैं । मेरे पास एक ही तरीका था, जो ऑफ़र थी, उसके बाद एक ही तरीका था जिस पर डिपार्टमेंट आफ़ पावर ने एक स्टेज पर विचार किया था । कि हम इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक के बाहर ले लें और वर्ल्ड बैंक के बाहर लेने के बाद हम कहीं और से संसाधन उपलब्ध करायें । वित्त मंत्रालय की यह राय थी कि अगर इसको वर्ल्ड बैंक से बाहर ले लिया तो इससे मिस प्रोक्योरमेंट का का इल्जाम आयेगा और हमारे जो दूसरे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स है वे इससे प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर, लेकिन मैं यह सफ़ाई नहीं दे रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं आपको सारे कागज उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूं, एक तो यह इल्जाम आयेगा और दूसरा यह होगा कि अगर हमने इसको वर्ल्ड बैंक से निकाला और कहीं और से संसाधन निकालने का प्रयास करेंगे तो इसमें 14 से लेकर 18 महीने की देरी हो जाएगी और इसके कारण हमारा पूरा पावर प्रोग्राम प्रभावित होगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over. Papers to be laid on the Table.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक के कार्यकाल का बढ़ाया जाना

***245. श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक के कार्यकाल को दूसरी बार बढ़ाये जाने तथा संस्थान से संबंधित कुछ अन्य मामलों के बारे में जून, 1990 में एक पत्र भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा यदि उस पर कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है और कार्यवाही कब की गई ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) कुछ संसद सदस्यों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की निदेशक की दूसरी बार सेवाएं बढ़ाने के संबंध में जून, 1990 में प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा था । संस्थान की वर्तमान निदेशक डा० (श्रीमती) स्नेह भार्गव को केन्द्रीय सरकार की अनुमति से उनकी 30 जून, 1990 को अधिवार्षितावय प्राप्त कर लेने तक 15 नवम्बर, 1989 को नियुक्त किया गया था । पहली बार डा० भार्गव को केन्द्रीय सरकार की अनुमति से 1 जुलाई, 1990 से 6 महीने की अवधि के लिए अथवा नए निदेशक का चयन हो जाने तक, जो भी पहले हो, सेवा विस्तार दिया गया था । ऐसा अपरिहार्य परिस्थितियों में किया गया था और यह संस्थान के नियमों और विनियमों के अनुसार है । नए निदेशक के चयन के लिए उपाय पहले ही शुरू कर दिए हैं और इस प्रक्रिया के शीघ्र ही पूरा हो जाने की संभावना है ।

पत्र में उठाए गए अन्य प्रमुख मुद्दे एन० एम० आर० (न्यूक्लियर मैगनेटिक रिसोनांस) के लिए उपकरण, कम्प्यूटरीकरण और सी० टी० वी० एस० (कार्डियो थोरेसिक और वास्कुलर सर्जरी) उपकरण खरीदने और चयन समिति के एक सदस्य की नियुक्ति से संबंधित हैं । अब तक की गई जांच से एन० एम० आर० कम्प्यूटरीकरण और सी० टी०वी०एस० लिए उपकरण खरीदने के संबंध में किन्हीं अनियमितताओं का पता नहीं चला । ऊपरलिखित चयन समिति का सदस्य 11 सदस्यों में से एक है और पूर्णतया अर्हता प्राप्त है ।

Price control on drugs

*246. SHRI RAJNI RANJAN SAHU:
CHOWDHARY RAM SEWAK:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether. Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the 'Indian Express' of the 14th August, 1990 under the heading "Total decontrol of drugs ruled out";

(b) if so, whether it is a fact that his Ministry included 26 bulk drugs under price control as none of these drugs fulfil any exclusive criteria laid down by the Kelkar Committee;

(c) whether it is a fact that all these drugs are having turn over of more than Rupees Fifty lakhs per annum which was one of the principles laid down for inclusion under price control;

(d) whether it is also a fact that there are more than fifty drugs which do not fulfil any exclusion criteria but have been exempted from, price control; and

(e) if so, what are the names of such drugs and what was the procedure adopted to pick up only 26 drugs while keeping others pending?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) Government has seen the news item which appeared in the Indian Express on 14-8-1990.

(b) and (c) Yes, Sir.

(d) and (e) A number of representations, most of which are from the Hon'ble Members of Parliament, have been received for wrong exclusion of about 165 bulk drus from price control under the Drugs (Prices Control) Order, 1987. In most of such representations, it has been alleged that excluded drugs do not fulfil any of the five exclusion criteria enunciated by the Kelkar Committee in its report. The inclusion of 26 bulk drugs under the Drugs (Prices Control) Order, 1987 is a part of the review of the DPCO., 1987 in the light of the aforesaid representations. The Standing Committee Constituted by the Department of Chemicals and Petrochemicals is looking into other cases.